



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुकवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 18 जुलाई, 2003

संख्या वि० स०-लैज-गवरनमेंट बिल/1-75/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का

विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2003 का विधेयक संख्यांक 13.

हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुर-स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1975 का 9

2. हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (क-ख) के पश्चात् नया खण्ड (क-ग) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन।

"(क-ग) "हल्के यान्त्रिक यान" से ऐसी मोटरकार या वैन या जीप या जिप्सी अभिप्रेत है, जिसका लदान रहित वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो; "।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, "अनुसूची" शब्द जहां-जहां आता है, के स्थान पर "अनुसूची-I" शब्द, बिन्हु और रोमन अंक रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

4. (1) मूल अधिनियम की शीर्षक सहित धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 13 का प्रति-स्थापन।

"13. छूट.—(1) अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों पर, इसके स्तम्भ (3) में दी गई शर्तों और अपवादों, यदि कोई हों, के अधीन किसी भी सड़क अवसंरचना के उपयोग के लिए कोई भी पथकर देय और प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अपने ऐसा करने के आशय का तीस दिन से अत्यन्त अवधि का नोटिस देने के पश्चात् ऐसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची-II में किसी भी यान को जोड़ या उसमें से उसे हटा सकेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुसूची-II तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा पटल पर रखी जाएगी।"

अनुसूची-II
का जोड़ना।

5. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान "अनुसूची" में, शीर्षक "अनुसूची" के स्थान पर, "अनुसूची-I" शीर्षक रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित "अनुसूची-II" जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-II"

(धारा 13 देखें)

क्रम संख्या	विशिष्टियां	शर्तें और अपवाद
1	2	3
1.	राष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवाओं, डिप्लोमैटिक कोर, हिमाचल प्रदेश सरकार, फायर टैंडरज और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से सम्बन्धित यान्त्रिक यान ;	—
2.	उप-राष्ट्रपति, मन्त्रियों, अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) से सम्बन्धित हल्के यान्त्रिक यान ;	—
3.	हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित संसद सदस्यों और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित हल्के यान्त्रिक यान ;	—
4.	रोगी वाहन और शारीरिक विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए विशेषतः डिजाईन्ड यान ;	—
5.	मोटर साइकिलें और स्कूटर ; और	—
6.	ट्रेक्टर	जब इनका कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाए।"

निरसन और
व्यावृत्ति।

6. (1) हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

2003 का
I

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 के अधीन हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों और हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित संसद सदस्यों के हल्के यान्त्रिक यानों पर भी पथकर उद्गृहीत किया जा रहा था। यह विचार करना आवश्यक हो गया था कि हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित संसद सदस्यों और हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों से सम्बन्धित हल्के यान्त्रिक यानों को पथकर के संदाय से छूट दी जाए। इसके अतिरिक्त छूट के उपबन्ध को दोषमुक्त और सुस्पष्ट बनाने के लिए उच्च न्यायालय के यान्त्रिक यानों को छूट की अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में उल्लेख किया जाना भी अनिवार्य समझा गया था। इस कारण उपर्युक्त अधिनियम में तुरन्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 में संशोधन किया जाना अनिवार्य था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) 8 अप्रैल, 2003 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे तारीख 9 अप्रैल, 2003 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीखजुलाई, 2003.

वित्तीय जापन

विधेयक का खण्ड 4 यान्त्रिक यानों द्वारा सड़क अवसंरचना के उपयोग के लिए पथकर के संदाय से छूट का उपबन्ध करता है, प्रस्तावित छूट में अन्तर्वर्तित सम्भाव्य हानि का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक की पारिणामिक हानि प्राक्कलित है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक का खण्ड 4 राज्य सरकार को अनुसूची-II में किसी भी यान को जोड़ने या उसमें से उसे हटाने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या : ई0 एक्स0 एन0-एफ (6) 1/2002-1]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2003 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए
विधेयक।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मंत्री।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख जुलाई, 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 2003

THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT)
BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL*further to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title
and com-
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2003.

Amend-
ment of
section 2.2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (herein-
after referred to as the "principal Act"), after clause (a-b), the
following new clause (a-c) shall be inserted, namely:—

9 of 1975.

“(a-c) “light mechanical vehicle” means a motor car or
van or jeep or gypsy the unladen weight of which does
not exceed 7500 kilograms ;”.Amendment
of section 3.3. In section 3 of the principal Act, for the word “Schedule”
wherever it occurs, the word, sign and roman figure “Schedule-I”
shall be substituted.Substitution
of section
13.4. (1) For section 13 of the principal Act, alongwith its heading,
the following shall be substituted, namely :—“13. *Exemptions.*—(1) No toll shall be payable and charged
on the vehicles specified in column (2) of the Schedule-II for the use of
any road infrastructure, subject to the conditions and exceptions, if
any, set out in column (3) thereof.(2) The State Government, after giving by notification not less
than thirty days notice of its intention so to do, may by like
notification, add to or delete any vehicle from the Schedule-II
and thereupon the said Schedule-II shall be deemed to be
amended accordingly.(3) Every notification issued under sub-section (2) shall, as
soon as may be, after it is issued, be laid on the Table
of the Legislative Assembly.”

5. In the existing SCHEDULE appended to the principal Act, for the heading "SCHEDULE", the heading "SCHEDULE-I" shall be substituted and thereafter the following SCHEDULE-II shall be added, namely:—

Addition
of Schedules
II.

"SCHEDULE-II

(See section 13)

Sl. No.	Particulars	Conditions and Exceptions
1	2	3
1.	The mechanical vehicles belonging to the President, Defence Services of the Union of India, Diplomatic Corps, the Himachal Pradesh Government, Fire Tenders and the High Court of Himachal Pradesh;	—
2.	The light mechanical vehicles belonging to the Vice-President, the Ministers, the Speaker and the Deputy Speaker;	—
3.	The light mechanical vehicles belonging to the Members of Parliament elected from Himachal Pradesh and the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;	—
4.	The ambulances and the vehicles specially designated for use by physically handicapped person;	—
5.	Motor cycles and Scooters; and	—
6.	Tractors	When used for agricultural purpose."

6. (1) The Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

Repeal and
saving

1 of 2003.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, the toll was being levied even on the light mechanical vehicles of the Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly, and the Members of Parliament elected from Himachal Pradesh. It was considered necessary to exempt the light mechanical vehicles from the payment of toll belonging to the Members of Parliament elected from Himachal Pradesh and the Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly. Further, in order to make exemption provisions clear and unambiguous, it was also considered essential to mention specifically the mechanical vehicles of the High Court in the Schedule of exemption. This had necessitated the immediate amendments in the Act *ibid*.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Ordinance, 2003 (H. P. Ordinance No. 1 of 2003) was promulgated under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 8th April, 2003, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 9th April, 2003. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance with modifications.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA : 17/10/02

Dated : July, 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 4 of the Bill seeks to provide exemptions from payment of tolls for the use of road-infrastructure, by mechanical vehicles, the likely loss involved in the proposed exemptions cannot be exactly quantified. Thus, the resultant loss is estimated to the tune of rupees 1.5 lakhs to 2 lakhs approximately annually.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

✓ Clause 4 of the Bill seeks to empower the State Government to add or delete any vehicles from Schedule-II. The proposed delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. EXN-F(6)1/2002-1]

The Governor, Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Bill, 2003, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT) BILL, 2003

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975).

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The.....2003.